डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

किसान कल्याण वर्ष-2026
समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 1 मई, 2026, डिस्पेच दिनांक 1 मई, 2026

| वर्ष 69 | अंक 23 | भोपाल | 1 मई, 2026 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

गेहूं उपार्जन में किसानों को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो : मुख्यमंत्री

किसान हितैषी निर्णयों से उपार्जन केन्द्रों पर बढ़ेगी आवक, कलेक्टर्स करें व्यवस्था सुनिश्चित

प्रतिदिन गेहूं खरीदी, परिवहन व्यवस्था, भंडारण तथा कृषकों के भुगतान की करें समीक्षा

चना और मसूर की खरीदी मण्डी शेड में करें ताकि असमय बारिश से नुकसान न हो

प्रदेश में पर्याप्त बन्दोबस्त है आवश्यक बारदानों का

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन करने के लिए माना आभार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की गेहूं उपार्जन की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों के हित में गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। लघु एवं सीमांत कृषकों के साथ-साथ मध्यम एवं बड़े किसानों के लिये भी स्लॉट बुकिंग प्रारम्भ कर दी गई है। उपार्जन केंद्रों की क्षमता 1000 क्विंटल प्रतिदिन से बढ़ाकर 2250 क्विंटल प्रतिदिन कर दी गई है। स्लॉट बुकिंग की तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 09 मई कर दी गई है। इन निर्णयों के परिणामस्वरूप किसानों की आवक केंद्रों पर अब तेजी से बढ़ेगी। कलेक्टर्स अपने-अपने जिलों में तद्नुसार प्रबन्ध सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंडियों में अपनी उपज बेचने आ रहे किसानों को समस्त प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हों और किसी भी प्रकार से तकलीफ न हो। उपार्जन केन्द्रों पर तौल कांटें, हम्माल, छाया, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी कलेक्टर्स प्रतिदिन गेहूं खरीदी, परिवहन व्यवस्था, भंडारण तथा कृषकों के भुगतान की आवश्यक रूप से समीक्षा करें। चना और मसूर की खरीदी मण्डी में शेड के अंदर की जाए ताकि असमय बारिश से नुकसान न हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चना-मसूर उपार्जन की व्यवस्था के संबंध में जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश में गेहूं उपार्जन की समीक्षा के दौरान यह निर्देश जिला कलेक्टर्स दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में आवश्यक बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर 7 दिवस की खरीदी के लिए बारदान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर न्यूनतम 6 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों की व्यवस्था हों और निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही गेहूं का उपार्जन किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उपार्जन केन्द्रों के अतिरिक्त कृषकों द्वारा मंडी में किए जा रहे उपज विक्रय की भी सतत् निगरानी की जाए, जिससे कृषकों को कोई समस्या न हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुना, रायसेन, दतिया, सीधी, विदिशा के कलेक्टर्स से वर्चुअली संवाद कर जिलों की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 3 हजार 516 उपार्जन केन्द्र संचालित हैं। कुल 8 लाख 55 हजार कृषकों द्वारा स्लॉट बुकिंग कराई गई है, जिनमें से 3 लाख 96 हजार कृषकों से 16 लाख 60 हजार मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित कर 2 हजार 527 करोड़ रूपए राशि का भुगतान किया जा चुका है। मध्यम एवं बड़े श्रेणी के 40 हजार 457 कृषकों द्वारा 5 लाख 88 हजार मीट्रिक टन मात्रा के स्लॉट बुक किए गए हैं। किसानों को तहसील के स्थान पर जिले के किसी भी उपार्जन केन्द्र पर उपज विक्रय की सुविधा दी गई है।

भारत सरकार द्वारा चमक विहीन गेहूं की सीमा में 50 प्रतिशत तक शिथिलता प्रदान की गई है। इसी प्रकार कम पानी के कारण अल्प विकसित दाने की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत और क्षतिग्रस्त दानों की सीमा 6 प्रतिशत बढ़ाई गई है। बैठक में कृषि मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक बर्णवाल तथा संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सहकारिता किसानों की आय, तकनीक और विश्वास में बढ़ोतरी का आधार बनी : मंत्री श्री सारंग

भोपाल : सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि मध्यप्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर रहा है। राज्य में पेक्स के डिजिटलीकरण, व्यवसाय विविधिकरण, सदस्यता विस्तार और दुग्ध संघों की प्रगति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी है।

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि प्रदेश की सभी 4536 कार्यशील पेक्स का सफल कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। ईआरपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यप्रणाली पारदर्शी और आधुनिक बनी है। किसानों को एसएमएस के जरिए लेन-देन की जानकारी देने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम है। साथ ही, ऑनलाइन और पेपरलेस सदस्यता सुविधा से किसानों को सरल और सुगम सेवाएं मिल रही हैं।

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि पेक्स अब पारंपरिक गतिविधियों से आगे बढ़कर नए व्यवसाय अपना रही हैं। आईएफएफसीओ-एमसी आउटलेट, सांची पार्लर, पशुचारा और रिटेल स्टोर जैसे नवाचारों से समितियों की आय में वृद्धि हो रही है। आगामी वर्षों में 1500 से अधिक पेक्स में व्यवसाय विविधिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 58 लाख से अधिक सदस्य हैं, जबकि 41 लाख नए सदस्य बनाने की अपार संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 10 लाख नए सदस्य बनाने का अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण, सस्ती कृषि सामग्री और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

दुग्ध संघों में ऐतिहासिक प्रगति

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि एनडीडीबी के साथ हुए समझौते के बाद प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूध उत्पादकों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया गया है और उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। नए डेयरी प्लांट और बल्क मिल्क कूलर की स्थापना से डेयरी क्षेत्र को नई गति मिली है।

सहकारिता से आत्मनिर्भरता की ओर

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों, महिलाओं और ग्रामीण समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार का उद्देश्य सहकारिता को जन-जन तक पहुंचाकर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है।

बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री डी.पी. आहूजा, उपसचिव श्रीमती रानी बाटड़, प्रबंध संचालक अपैक्स बैंक श्री मनोज गुप्ता, प्रबंध संचालक राज्य सहकारी संघ श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक बीज निगम श्री महेंद्र दीक्षित सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश में सहकार से हो रहा है डेयरी गतिविधियों का विस्तार : डॉ. यादव

- डेयरी गतिविधियों में 26 हजार गांवों को जोड़ने और प्रतिदिन 52 लाख कि.ग्रा. दुग्ध संकलन का लक्ष्य
- दुग्ध क्षेत्र में पारदर्शिता और ब्रांड सुदृढ़ीकरण पर होगा विशेष फोकस
- दुग्ध समितियों में महिला सदस्यता को किया जाए प्रोत्साहित
- मोबाइल ऐप से होगा दुग्ध संकलन
- जिला स्तर पर कार्यक्रमों में होगा आदर्श पशुपालकों का सम्मान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई म.प्र. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन से जुड़ी गतिविधियां किसानों की आय बढ़ाने में प्रभावी रूप से सहायक है। किसानों की आय दोगुना करने के लिए किसान कल्याण वर्ष में राज्य सरकार डेयरी गतिविधियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के दुग्ध संघों को दिए जा रहे सहयोग से दुग्ध संकलन में वृद्धि हुई है और किसानों को भी दूध के बेहतर दाम मिल रहे हैं। सहकार के भाव से डेयरी गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। दुग्ध समितियों में महिला सदस्यता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। डेयरी सहकारी कवरेज के विस्तार और सुदृढ़ीकरण, नई डेयरी प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण और पशु चारा संयंत्र के आधुनिकीकरण, डेयरी वैल्यू चैन के डिजीट्लाइजेशन, पारदर्शिता और दुग्ध उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए कार्ययोजना बनाई जाए। डेयरी विकास योजना के अंतर्गत 26 हजार गांवो को जोड़ने, प्रतिदिन दुग्ध संकलन 52 लाख किलोग्राम तक करने का लक्ष्य रख, गतिविधियां संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ये निर्देश मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की राज्य स्तरीय संचालन समिति की द्वितीय बैठक में दिए।

मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में हुई बैठक में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री श्री लखन पटेल, वरिष्ठ विधायक तथा वरिष्ठ विधायक एवं अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन तथा अध्यक्ष नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड श्री मीनेष शाह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध क्षेत्र में अनुभव का लाभ राजधानी से लेकर ग्राम स्तर तक सुनिश्चित किया जाए। दूध और दुग्ध उत्पादों के बिक्री में सुधार के लिए ब्राण्ड सुदृढ़ीकरण और नई पैकेजिंग डिजाइन कर उत्पादों की पहुंच का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दुग्ध उत्पादन में वद्धि और विभिन्न दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए किसानों को नवाचार करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों तथा प्रदेश के युवाओं को डेयरी टेक्नोलॉजी की नई तकनीकों से परिचित कराने की भी आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आदर्श पशुपालकों को सम्मानित करने, दूधारू पशुओं की प्रदर्शनी आयोजित करने और डेयरी के संबंध में सूचना सम्प्रेषण के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और दुग्ध संघों का कार्यअनुबंध करने के बाद वर्ष 2025-26 में 1752 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया तथा 701 निष्क्रिय दुग्ध समितियों को क्रियाशील किया गया। प्रदेश में प्रतिदिन 9 लाख 67 हजार कि.ग्रा. दुग्ध संकलन किया जा रहा है, साथ ही 153 नवीन बल्क मिल्क कूलर की स्थापना की गई है। दूध और दूध उत्पादों का क्रेडिट पर विक्रय बन्द कर दिया गया है। प्रदेश में दुग्ध संकलन मोबाइल ऐप से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से दुग्ध प्रदायकों को दूध की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्य की जानकारी तत्काल प्राप्त हो सकेगी। क्षेत्र संचालन तथा विपणन कार्य में लगे मैदानी अमले की मॉनीटरिंग के लिए फील्ड फोर्स मॉनीटरिंग ऐप आरंभ किया गया है।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में दूध की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन में हानि को कम करने और एक समान उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है। इंदौर में स्थापित 30 मीट्रिक टन क्षमता का दुग्ध चूर्ण संयंत्र आरंभ किया जा चुका है।

शिवपुरी में 20 हजार लीटर क्षमता के डेयरी संयंत्र और ग्वालियर डेयरी संयंत्र के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। पशु आहार संयंत्रों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए विशेष व्यवस्था लागू की गई है। पीपीपी मोड पर भी प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास श्री उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री डी. पी. आहूजा, सहित राज्य सरकार और एनडीडीबी के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायसेन उन्नत कृषि महोत्सव : 'बीज से बाजार तक'

दिल्ली, किसानों के लिए खेती को अधिक आधुनिक, लागत-प्रभावी एवं उत्पादनमुखी बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के रायसेन में तीन दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन 11-13 अप्रैल के बीच किया गया।

उन्नत कृषि महोत्सव में किसान भाई बहनों लिए कृषि एवं संबद्ध विषयों पर 24 प्रशिक्षण एवं सेमिनार के सत्र आयोजित किए गए। इनमें किसानों के साथ-साथ कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने भी सक्रिय सहभागिता की। यह एक इंटरैक्टिव सत्र था जिसमें किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों, कृषि और संबद्ध विभाग के अधिकारियों से सत्र के दौरान ही अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। किसान भाई बहनों को यहां नवीन कृषि तकनीकों एवं उन्नत पद्धतियों की भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

इन सत्रों के माध्यम से किसानों को यह बताया गया कि किस प्रकार Integrated farming, Polyhouse इत्यादि से खेती की अधिक समृद्धशाली बनाया जा सकता है जिससे यह केवल जीविका नहीं, बल्कि लाभ का सशक्त पेशा बन सके।

रायसेन का 'उन्नत कृषि महोत्सव' इस वजह से भी विशेष रहा कि इन सत्रों के माध्यम से किसानों ने न सिर्फ कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलाप में अपना ज्ञानवर्धन किया, बल्कि इसमें शामिल होने देशभर से आए वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों ने भी किसानों से संवाद के जरिए कृषि कार्य की नई- नई चीजों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया।

महोत्सव के दौरान आयोजित KVK सम्मेलन, FPO सम्मेलन के साथ विभिन्न सत्रों में- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, हाइड्रोपोनिक्स, बागवानी, फूलों की खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, दलहन एवं तिलहन में उत्पादकता वृद्धि तथा कृषि मशीनीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। इस प्रकार किसानों को 'बीज से बाजार तक' की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की गई।

सोमवार को समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्नत कृषि महोत्सव केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने इसे किसानों के लिए एक ऐसा मंच बताया, जहाँ व्यावहारिक ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और विकास एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु, जल उपलब्धता एवं संसाधनों के आधार पर 'बीज से बाजार तक' का एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है, जिससे उपयुक्त फसलों, फलों एवं सब्जियों की पहचान कर उनके उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन की समग्र योजना बनाई जा सकेगी।

महोत्सव में लगभग 350 स्टॉल लगाए गए, जहां विभिन्न कृषि तकनीकों, उपकरणों एवं योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लगभग 4000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1800 कार्ड मौके पर ही स्वीकृत कर वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनियों द्वारा सरल एवं प्रभावी तरीके से किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु जागरूकता अभियान भी चलाया गया।

किसान सिर्फ अन्न नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था उगाता है- राजनाथ सिंह

रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव का आगाज़, हजारों किसानों का महासंगम

बिचौलिया–मुक्त बाजार, सुरक्षित उपज, समृद्ध किसान हमारा लक्ष्य- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

छोटे किसान को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से दो लाख वार्षिक आमदनी संभव- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

कृषि रोडमैप से रायसेन–विदिशा–सीहोर–देवास को हॉर्टिकल्चर और दलहन हब बनाया जाएगा- श्री शिवराज सिंह

रायसेन की पवित्र धरा पर सभा या रैली नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और किसान का महासंगम हो रहा है- श्री शिवराज सिंह

सीमा पर जवान, खेत में किसान– दोनों का सम्मान बराबर- मुख्यमंत्री मोहन यादव

रायसेन कृषि मेले में कॉर्न कटर, ड्रोन, माइक्रो इरिगेशन से लेकर पशुपालन तक का लाइव टेक्नोलॉजी डेमो

वेयरहाउस–कोल्ड स्टोरेज, मृदा ऐप और 20 टेक्निकल सत्रों से किसानों को 'वन–स्टॉप' समाधान

दिल्ली, रायसेन (मध्य प्रदेश) में शुरू हुए तीन दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव, प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का भव्य शुभारंभ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, जहाँ मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हजारों किसान, कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के प्रतिनिधि एक मंच पर जुटे।

किसान की मेहनत और संघर्ष को दिल से समझते हैं- राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मंच से सबसे पहले रायसेन की धरती पर उपस्थित अन्नदाता बहनों–भाइयों को सिर झुकाकर नमन करते हुए कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और गाँव की मिट्टी में पले–बढ़े हैं, इसलिए किसान की मेहनत और संघर्ष को दिल से समझते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि रायसेन में आयोजित यह उन्नत कृषि महोत्सव हमारे किसान भाइयों–बहनों के लिए केवल लाभदायक ही नहीं, बल्कि उनके जीवन की तस्वीर बदलने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करते हुए कहा कि किसान के हित में इतना केंद्रित और विषयगत आयोजन वास्तव में सराहनीय है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमेशा किसानों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हैं, और यह केवल कहने की बात नहीं, बल्कि पिछले वर्षों में जमीन पर हुए बेमिसाल कार्यों से साबित तथ्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले अगर किसान के नाम पर पैसा निकलता था तो आधा रास्ते में ही दूसरों की जेब में चला जाता था, जबकि अब सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि दिल्ली से जितना पैसा निकलता है, वह पूरा का पूरा सीधे किसान के खाते में पहुँचता है- बिना बिचौलिया, बिना कट, बिना झंझट। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक सहायता कोई दान नहीं, बल्कि किसान के पसीने और परिश्रम का सम्मान है जिससे वह बीज, खाद और खेत के जरूरी खर्च पूरे कर पाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोखिम भरी खेती के लिए अनमोल सुरक्षा कवच बताते हुए कहा कि अब ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा या कीट–प्रकोप जैसी विपदाओं में फसल खराब होने पर सीधा मुआवजा किसान के खाते में जाता है, जिससे उनकी कमर न टूटे, हताशा–निराशा की जगह फिर से खड़े होने का हौसला मिले। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जिक्र करते हुए कहा कि अब किसान अपनी मिट्टी की जांच कर जमीन की जरूरत के हिसाब से ही खाद डालते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है और लागत घटती है।

अगर किसान गेहूँ ही न उगाए तो पूरी चेन डगमगा जाएगी

रक्षा मंत्री ने कहा कि किसान केवल अन्न नहीं उगाता, वह पूरी अर्थव्यवस्था, रोजगार और उद्योग–धंधों को उगाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक (खेती–पशुपालन), द्वितीयक (उद्योग) और तृतीयक (सेवाएँ) तीनों क्षेत्रों की जड़ें किसान की जमीन से जुड़ी हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि किसान गेहूँ उगाता है, वही गेहूँ ट्रक से मंडी तक जाता है, आटा मिल में प्रोसेस होकर बिस्कुट–ब्रेड फैक्ट्रियों तक पहुँचता है, वहाँ मजदूर और मशीनें काम करते हैं, फिर पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और दुकानों के जरिए वह उत्पाद उपभोक्ता तक पहुँचता है- यानी अगर किसान गेहूँ ही न उगाए तो पूरी चेन डगमगा जाएगी। उन्होंने कहा कि इसीलिए वे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि किसान पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है और सरकार खेती को गर्व का विषय बनाने तथा किसान को पूरी आन–बान–शान के साथ जीवन जीने योग्य बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे ड्रोन, सेंसर, मोबाइल तकनीक, स्मार्ट फार्मिंग, बिना मिट्टी की खेती, संरक्षित खेती, बागवानी और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप और नवाचार के साथ कृषि से जुड़ें, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं और गाँव का नौजवान जितना जुड़ता जाएगा, उतनी ही नई तकनीक और अधिक आमदनी के रास्ते खुलते जाएँगे। उन्होंने यह भी बताया कि रक्षा मंत्रालय ने कैंटोनमेंट क्षेत्रों में आसपास के किसानों से ही जैविक सब्जियाँ और श्री अन्न (ज्वार, बाजरा, रागी) खरीदने की पहल की है, जिससे किसानों की आय बढ़ रही है और जवानों को ताज़ा, पौष्टिक भोजन मिल रहा है, और इस तरह 'जय जवान, जय किसान' के नारे को नए अर्थ के साथ चरितार्थ किया जा रहा है।

रायसेन की रीति, नीति, प्रीति, पहचान, शान और यहाँ की जनता की मुस्कान तक निराली है

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रायसेन की इस पवित्र धरा पर आज केवल सभा या रैली नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और किसान का महासंगम हो रहा है, जहाँ आधुनिक तकनीक, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक अनुसंधान और आधुनिक कृषि पद्धतियों को देखने–समझने और सीखने का अनोखा अवसर मिलेगा। उन्होंने रायसेन को अद्भुत बताते हुए कहा कि रायसेन की रीति, नीति, प्रीति, पहचान, शान और यहाँ की जनता की मुस्कान तक निराली है, यहाँ के धान और गेहूँ ने विश्व–स्तर पर अलग पहचान बनाई है और सांची–भीमबेटका जैसे दो विश्व धरोहर स्थल, भोजपुर का विशाल शिवलिंग और नर्मदा–बेतवा की पावन धाराएँ इस जिले की गरिमा बढ़ाती हैं।

आत्मनिर्भर भारत बनाने के महायज्ञ में रक्षा और कृषि दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण स्तंभ हैं

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित, समृद्ध, गौरवशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने का महायज्ञ चल रहा है, जिसमें रक्षा और कृषि दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मजबूत हुई देश की सुरक्षा व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भारत की स्पष्ट नीति है- हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन यदि कोई हमें छेड़ेगा तो उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा और इसी मजबूत रक्षा–नीति के साथ किसान और कृषि के विकास का बड़ा अभियान भी पूरी शिद्दत से चल रहा है।

किसान ही भगवान और जनता ही जनार्दन है

उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि वे जिस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ की जनता ने उन्हें छह विधानसभा और छह लोकसभा सहित कुल 12 चुनाव जिताए हैं, इसलिए उनके लिए किसान ही भगवान और जनता ही जनार्दन है, जिनकी सेवा ही उनके लिए भगवान की पूजा के समान है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, 140 करोड़ भारतीयों के हर पेट तक पोषण–युक्त अनाज, फल–सब्जियाँ पहुँचाना और विदेशों पर निर्भरता कम करना सरकार की स्पष्ट प्राथमिकता है। इसलिए कृषि में उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और कृषि का विविधीकरण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे-चौहान

रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव का भव्य समापन, हजारों किसानों के साथ कृषि बदलाव का नया संकल्प

शिवराज सिंह चौहान की मांग पर नितिन गडकरी की बड़ी सौगात, रायसेन रिंग रोड और सौंदर्यीकरण कार्यों को मिली मंजूरी

किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता और हाइड्रोजन दाता भी बनेगा- नितिन गडकरी

एआई, ड्रोन, नैनो यूरिया और नवाचार से घटेगी लागत, बढ़ेगा उत्पादन- नितिन गडकरी

जल संरक्षण, डेयरी, मत्स्य और प्रोसेसिंग से बढ़ेगी किसानों की आमदनी- नितिन गडकरी

यह समापन नहीं, नई शुरुआत है; रोडमैप को जमीन पर उतारेंगे- शिवराज सिंह चौहान

बीज से बाजार तक की योजना पर अमल के लिए बनेगी टास्क फोर्स- शिवराज सिंह चौहान

दिल्ली, राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कृषि मेले "उन्नत कृषि महोत्सव" का रायसेन में अत्यंत उत्साह, उमंग, नवाचार और हजारों किसानों की गरिमामयी उपस्थिति के बीच भव्य समापन हुआ। समापन सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने जहां सड़क विकास, कृषि तकनीक, जल संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा और ग्रामीण समृद्धि का व्यापक विजन रखा, वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बीज से बाजार तक तैयार रोडमैप को जमीन पर उतारने का दृढ़ संकल्प दोहराया।

शिवराज सिंह चौहान द्वारा रखी गई क्षेत्रीय मांगों पर महत्वपूर्ण घोषणाएँ

रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर आयोजित "उन्नत कृषि महोत्सव" के समापन सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रखी गई क्षेत्रीय मांगों पर महत्वपूर्ण घोषणाएँ करते हुए विकास की नई सौगात दी। उन्होंने रायसेन रिंग रोड/पूर्वी बायपास के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने, संबंधित डीपीआर तैयार करने, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए जाने और पुलों के सौंदर्यीकरण संबंधी मांगों पर सकारात्मक सहमति व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य सड़क संबंधी प्रस्तावों पर भी जो संभव सहयोग होगा, वह किया जाएगा।

ज्ञान को संपत्ति में बदलना आज कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है

अपने संबोधन में श्री गडकरी ने कहा कि वे इस कार्यक्रम में मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि किसान के रूप में आए हैं। उन्होंने कहा कि खेती का भविष्य अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेदर स्टेशन, सैटेलाइट आधारित सूचना, ड्रोन, नैनो यूरिया और आधुनिक कृषि तकनीकों से जुड़ चुका है, इसलिए किसानों को समय के साथ बदलना होगा। उन्होंने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और ज्ञान को संपत्ति में बदलना आज कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने किसानों से इनोवेशन, रिसर्च, सफल प्रयोगों और तकनीक-आधारित खेती को अपनाने का आह्वान किया, ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन संभव हो सके।

श्री गडकरी ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, डामर दाता और हाइड्रोजन दाता भी बनेगा। उन्होंने कहा कि कृषि अवशेष, पराली, बायोमास, इथेनॉल, सीएनजी और हाइड्रोजन के माध्यम से किसानों के लिए आय के नए रास्ते खुलेंगे, आयात घटेगा और गांवों की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी।

जल संरक्षण पर विशेष बल

जल संरक्षण पर विशेष बल देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि दौड़ते हुए पानी को चलने के लिए, चलने वाले पानी को रुकने के लिए और रुके हुए पानी को जमीन को पिलाने के लिए लगाना होगा। उन्होंने "गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में" का संदेश देते हुए कहा कि जैसे पैसा बैंक में जमा किया जाता है, वैसे ही पानी को जमीन में डिपॉजिट करना होगा।

उन्होंने कहा कि जहां सिंचाई का पानी सीधे नहीं पहुँच सकता, वहां जल संरक्षण की संरचनाएँ बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।

उन्होंने डेयरी, मत्स्य पालन और ब्लू इकोनॉमी को किसानों की आय बढ़ाने के बड़े माध्यम बताते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। श्री गडकरी ने कहा कि केवल उत्पादन बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि प्रोसेसिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, प्री-कूलिंग सिस्टम और वैल्यू एडिशन की मजबूत व्यवस्था भी बनानी होगी। उन्होंने कहा कि जब बाजार में उत्पादन अधिक होता है तो कीमतें गिर जाती हैं, इसलिए भंडारण और प्रसंस्करण की मजबूत व्यवस्था किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए आवश्यक है।

उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे मेले में लगे स्टॉल, मशीनरी प्रदर्शन, पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस, हाइड्रोपोनिक्स, एक एकड़ खेती के मॉडल, बकरी पालन, मछली पालन और अन्य तकनीकी सत्रों को देखकर जाएँ, सीखकर जाएँ और उसे खेत में लागू करें। उन्होंने कहा कि यही ज्ञान, यही तकनीक और यही प्रयोग किसानों का भविष्य बदलेंगे, गांवों को समृद्ध बनाएंगे और स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट विलेज की दिशा को मजबूत करेंगे।

शिवराज सिंह के मुख्यमंत्रीत्व कार्यकाल की म.प्र. की कृषि उपलब्धियों की सराहना

श्री गडकरी ने शिवराज सिंह के मुख्यमंत्रीत्व कार्यकाल में मध्य प्रदेश की कृषि उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि किसानों को उन्नत बनाने के लिए इस तरह के आयोजन बेहद महत्वपूर्ण हैं और यह महोत्सव किसानों को भविष्य की नई प्रेरणा देने वाला सिद्ध होगा।

यह समापन नहीं, बल्कि नई शुरुआत है

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "उन्नत कृषि महोत्सव" कोई कर्मकांड नहीं है और यह समापन नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। उन्होंने कहा कि चार दिनों तक चले इस आयोजन ने किसानों के लिए पाठशाला का काम किया, जहाँ मिट्टी की महक, मशीन की शक्ति, नवाचार, तकनीक और विकास का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री चौहान ने कहा कि इस क्षेत्र की माटी, जलवायु, जल उपलब्धता और संसाधनों के आधार पर बीज से बाजार तक का विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस रोडमैप में यह तय किया गया है कि इस क्षेत्र में कौन-कौन सी फसलें, फल और सब्जियाँ अच्छी हो सकती हैं और उनके उत्पादन, प्रोसेसिंग तथा मार्केटिंग की संपूर्ण योजना कैसे बनेगी।

दलहन और बागवानी क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि अच्छे बीज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर ब्लॉक में बीज ग्राम बनाए जाएंगे, दलहन और बागवानी क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा और इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी की एक-एक बूंद का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा तथा कस्टम हायरिंग सेंटर और पंचायतों में मशीन बैंक बनाए जाएंगे, ताकि किसानों को आधुनिक मशीनें आसानी से मिल सकें। श्री चौहान ने कहा कि अच्छी नर्सरी और क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे, एफपीओ को मजबूत किया जाएगा, बैक हाउस और कोल्ड हाउस बनाए जाएंगे और किसानों को उत्पादन से बाजार तक बेहतर ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि एकीकृत खेती के मॉडल के माध्यम से छोटे खेत के टुकड़े पर भी अधिक आमदनी प्राप्त की जा सकती है और सरकार किसानों की आय बढ़ाकर ही चैन की सांस लेगी।

रोडमैप की मॉनिटरिंग के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे रोडमैप की मॉनिटरिंग के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी तथा राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर यह सुनिश्चित करेंगी कि जो संकल्प लिए गए हैं, वे केवल घोषणा बनकर न रह जाएँ, बल्कि पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतरें।

किसानों से फार्मर आईडी बनवाने की अपील

श्री चौहान ने किसानों से फार्मर आईडी बनवाने की अपील करते हुए कहा कि भविष्य में खेती से जुड़ी अनेक सेवाएँ, योजनाएँ और प्रक्रियाएँ इससे आसान होंगी। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जिंदगी बदलने, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण में कृषि को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा

अपने संबोधन में श्री चौहान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत करते हुए कहा कि वे ऐसे मंत्री हैं जो असंभव को संभव करके दिखाते हैं, नई तकनीक और नवाचार से देश में समृद्धि लाने का काम करते हैं और समयबद्ध कार्यशैली के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण में कृषि को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा और किसानों की सेवा ही सरकार के लिए सर्वोच्च दायित्व है।

किसानों को हितलाभों का वितरण

समापन सत्र में किसानों को हितलाभों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर और हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, श्री नारायण सिंह पवार, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी, विधायक डॉ. सुरेन्द्र चौधरी, श्री रमाकांत भार्गव, श्री हरि सिंह रघुवंशी, श्री हरि सिंह सप्रे, श्री मुकेश टंडन, श्री गोपाल सिंह इंजीनियर, श्री आशीष शर्मा, अन्य जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी तथा हजारों किसान भाई-बहन उपस्थित रहे।

किसानों के हित में केंद्र पूरी तरह सतर्क: कृषि मंत्री श्री सिंह

चौहान ने की खरीफ तैयारियों की समीक्षा

समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा- हमारे लिए किसान हित सर्वोपरि, संभावित अल नीनो प्रभाव को लेकर सरकार तैयार

मानसून पूर्वानुमान के बीच कृषि मंत्रालय की तैयारी: पानी, बीज और अन्य बातों को लेकर श्री शिवराज सिंह ने दिए दिशा-निर्देश

बेहतर जल भंडारण और समय पर तैयारी से केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में खरीफ पर असर सीमित रखने की रणनीति

दिल्ली | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति तथा आगामी खरीफ मौसम की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए कृषि सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मौसम पूर्वानुमान, जल उपलब्धता, फसलों की स्थिति, बीज एवं अन्य कृषि आदानों की व्यवस्था, राज्यों की तैयारियों तथा संभावित प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों से निपटने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हमारे लिए किसान हित सर्वोपरि है और संभावित अल नीनो प्रभाव को लेकर सरकार तैयार है।

बैठक में बताया गया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने वर्ष 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य से कम रहने की संभावना व्यक्त की है और मौसमी वर्षा देशभर में दीर्घकालीन औसत के लगभग 92 प्रतिशत रहने का अनुमान है। साथ ही यह भी संकेत दिया गया है कि मानसून सीजन के दौरान अल नीनो की स्थिति विकसित हो सकती है, हालांकि अंतिम और अद्यतन आकलन मई 2026 के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा के दौरान स्पष्ट किया कि मौसम संबंधी पूर्वानुमान को गंभीरता से लेते हुए सरकार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और किसानों को किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयास, बेहतर जल प्रबंधन, उन्नत तकनीक, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जलवायु-सहनशील कृषि उपायों के कारण संभावित चुनौतियों का प्रभाव काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

बैठक में यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखा गया कि वर्तमान समय में देश के जलाशयों का जलस्तर संतोषजनक स्थिति में है और समग्र भंडारण सामान्य से बेहतर है। उपलब्ध आकलन के अनुसार जलाशयों का भंडारण इस अवधि के सामान्य स्तर के 127.01 प्रतिशत पर है, जिससे खरीफ मौसम में सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और नमी की कमी के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। इस आधार पर बैठक में यह आकलन व्यक्त किया गया कि संभावित अल नीनो प्रभाव के बावजूद कृषि क्षेत्र पर इसका असर पहले की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित रहने की संभावना है। विशेष रूप से बेहतर जल उपलब्धता, सूक्ष्म सिंचाई, वैज्ञानिक सलाह, फसल विविधीकरण और समय पर हस्तक्षेप के कारण खेती अब पहले की अपेक्षा अधिक सक्षम और अनुकूलनशील बनी है।

समीक्षा के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि वर्ष 2000 से 2016 के बीच अल नीनो का प्रभाव कृषि उत्पादन पर अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखता था, क्योंकि उस समय वर्षा-निर्भरता अधिक थी और जलवायु जोखिमों से निपटने की व्यवस्थाएं वर्तमान की तुलना में सीमित थीं। हाल के वर्षों में तकनीकी प्रगति, बेहतर कृषि प्रबंधन, जल संरक्षण, सिंचाई नेटवर्क के विस्तार और उन्नत बीजों के उपयोग से फसलों की उत्पादकता में अधिक स्थिरता आई है। बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि कुछ फसलें, विशेषकर धान, अपेक्षाकृत अधिक स्थिरता दिखाती हैं, जबकि अन्य फसलों के लिए भी उपयुक्त प्रबंधन उपाय पहले से तैयार किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार का जोर इस बात पर है कि क्षेत्र-विशिष्ट और फसल-विशिष्ट रणनीति अपनाकर किसानों को समय पर सलाह, बीज, संसाधन और विकल्प उपलब्ध कराए जाएं।

कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी राज्य किसी भी विपरीत मौसम की स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण तैयारी रखें और जिला स्तर तक आकस्मिक योजनाओं को सक्रिय किया जाए। उन्होंने कहा कि बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ वैकल्पिक फसल विकल्प, देरी से बुवाई की रणनीति और सूखा-सहनशील किस्मों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि किसानों को व्यवहारिक और त्वरित समाधान मिल सकें। बैठक में यह भी बताया गया कि खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए बीज उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है तथा आकस्मिक स्थितियों के लिए राष्ट्रीय बीज रिजर्व की व्यवस्था भी रखी गई है। यह तैयारी इस उद्देश्य से की गई है कि यदि किसी क्षेत्र में मौसम का प्रतिकूल प्रभाव दिखे तो वहां वैकल्पिक बीज और उपयुक्त किस्में तुरंत उपलब्ध कराई जा सकें। श्री चौहान ने स्पष्ट किया कि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई से बचाने के लिए निगरानी तंत्र सक्रिय है और स्थिति की नियमित समीक्षा की जा रही है। राज्यों के साथ सतत समन्वय, फसल मौसम निगरानी, जिला कृषि आकस्मिक योजनाओं का अद्यतन और संकट प्रबंधन संबंधी संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से समय पर निर्णय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य केवल संभावित जोखिम का आकलन करना नहीं बल्कि समय रहते ऐसे सभी कदम उठाना है जिससे किसानों का आत्मविश्वास बना रहे, खेती की निरंतरता प्रभावित न हो और खरीफ सीजन सुचारु रूप से आगे बढ़े। उन्होंने भरोसा जताया कि बेहतर जल प्रबंधन, तकनीकी विकास, उन्नत कृषि पद्धतियों और समय पर की गई तैयारियों के बल पर संभावित चुनौतियों का प्रभाव कम किया जा सकेगा और किसानों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी।

क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों के बीच हर गाँव तक आधुनिक कृषि मशीनरी पहुँचाएँगे - श्री शिवराज सिंह चौहान

दिल्ली, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हर क्षेत्र के किसानों को उन्नत किस्में, सही फसल अनुशंसा और आधुनिक कृषि यंत्रों की सुलभ सुविधा एक साथ उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे कम लागत में, अधिक उत्पादन के साथ सुरक्षित और टिकाऊ खेती कर सकें। यह बात उन्होंने आज उन्नत कृषि महोत्सव के अवसर पर मीडिया से अनौपचारिक चर्चा के दौरान कहीं।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि क्लाइमेट चेंज अब बहुत प्रॉमिनेंट हो चुका है और अनसीज़नल बारिश, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तथा तापमान में अनिश्चितता के कारण खेती पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक संस्थान ऐसी फसल किस्में विकसित कर रहे हैं, जो अधिक गर्मी भी सह सकें, ज्यादा पानी की स्थिति में भी टिकाऊ रहें और कम पानी की स्थिति में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें, और इन वैरायटीज़ को तेजी से किसानों तक पहुँचाने के प्रयास जारी हैं।

श्री शिवराज सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार का फोकस केवल व्यक्तिगत मशीन सब्सिडी तक सीमित नहीं बल्कि गाँव स्तरपर साझा उपयोग के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक का नेटवर्क विकसित करना है। उन्होंने कहा कि पंचायतों, किसान समूहों, एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऐसे सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ से छोटे और सीमांत किसान भी किराये पर आधुनिक कृषि उपकरण ले सकें। उन्होंने बताया कि केंद्र की सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (SMAM) जैसी योजनाओं के तहत परियोजना लागत पर 40 से 80 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि लगभग 30 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर भी पंचायतों और किसान संगठनों को मजबूत समर्थन मिल सके। मीडिया के एक सवाल पर कि क्या एमपी लैड्स (MPLADS) की निधि से भी कस्टम हायरिंग सेंटर जिम की तरह बनवाए जा सकते हैं, श्री चौहान ने साफ कहा कि एमपी लैड्स का उद्देश्य स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियाँ बनाना है, जैसे सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य, खेल सुविधाएँ और स्थिर जिम आदि, जबकि कस्टम हायरिंग सेंटर संचालन और किराये के मॉडल पर आधारित होते हैं, जिनके लिए अलग प्रकार की व्यवस्था और संचालन ढांचा चाहिए। उन्होंने कहा कि कस्टम हायरिंग सेंटरों को हम MPLADS से नहीं, बल्कि कृषि मशीनीकरण और संबंधित योजनाओं से ही बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि नीति की भावना और पारदर्शिता दोनों बनी रहे।

श्री चौहान ने यह भी कहा कि भले ही एमपी लैड्स से सीधे कस्टम हायरिंग सेंटर न बनते हों, लेकिन सांसद और विधायक अपने क्षेत्रों में कृषि मशीनीकरण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे किसान समूहों, एफपीओ और पंचायतों के प्रस्तावों को राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाकर, स्वीकृति, निगरानी और समस्याओं के समाधान में सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से ही योजनाओं का लाभ सही मायने में अंतिम छोर के किसान तक पहुँचता है।

(पृष्ठ 3 का शेष)

किसान सिर्फ अन्न नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था...

किसान केवल पारंपरिक अनाज–प्रधान खेती से आगे बढ़कर एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाएँ

उन्होंने रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास के किसानों से आग्रह किया कि वे केवल पारंपरिक अनाज–प्रधान खेती से आगे बढ़कर एकीकृत कृषि प्रणाली (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) अपनाएँ, क्योंकि जमीन के छोटे–छोटे टुकड़ों- एक, दो या तीन एकड़ पर भी अगर अनाज के साथ फल, सब्जी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन जोड़ा जाए, तो वास्तविक रूप से लाभकारी खेती संभव है। उन्होंने बताया कि इस उन्नत कृषि महोत्सव में एक एकड़ के सम्पूर्ण इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल का लाइव डेमो लगाया गया है, और वैज्ञानिक मार्गदर्शन में इस मॉडल को अपनाने पर किसान एक एकड़ में भी दो लाख रुपये से अधिक की आमदनी कमा सकते हैं।

इस मेले को मात्र भाषण–कार्यक्रम की बजाय पाठशाला के रूप में तैयार किया गया है

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस मेले को मात्र भाषण–कार्यक्रम की बजाय पाठशाला के रूप में तैयार किया गया है जहाँ देश के शीर्ष वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और उन्नतशील किसान अलग–अलग हॉलों में लगभग 20 विषयों पर सत्र लेंगे- हॉर्टिकल्चर, बागवानी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मशीनों के उपयोग से लागत घटाने, ड्रोन के बहुआयामी उपयोग, बाज़ार से जुड़ाव और मिट्टी परीक्षण जैसे विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब 4000 किसानों ने इन सत्रों के लिए पंजीकरण कराया है, जहाँ वैज्ञानिक पहले प्रेजेंटेशन देंगे, फिर किसान खुलकर सवाल पूछ सकेंगे, और यही इस मेले की विशेषता है कि यह तमाशा नहीं, खेती की दशा–दिशा बदलने का ठोस प्रयास है।

केंद्र सरकार हर राज्य का कृषि रोडमैप तैयार कर रही है

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्र सरकार हर राज्य का कृषि रोडमैप तैयार कर रही है, क्योंकि हर राज्य की परिस्थितियाँ और एग्रो–क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए भी राज्य सरकार के साथ मिलकर एक समग्र कृषि रोडमैप बनाया जाएगा, जबकि रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास इन चार जिलों के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने विशेष कृषि रोडमैप तैयार किया है, जिसे कल दोपहर 1 बजे यहाँ औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा। इस रोडमैप में किस क्षेत्र में कौन–सी फसल, कौन–सा हॉर्टिकल्चर, कौन–सी दलहन–फसल, कौन–सी बीज किस्म और यदि किसान बागवानी करना चाहें तो कौन–से पौधे लगाने चाहिए; इसका पूरा वैज्ञानिक खाका दिया गया है।

रोडमैप को जमीन पर लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी

श्री शिवराज सिंह ने आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के समन्वय से इस रोडमैप को जमीन पर लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि यह कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि किसानों की जिंदगी बदलने का वास्तविक प्रयास है।

म.प्र. में 55 दाल मिलें खोलने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर हब बनाने की है, जहाँ अनेक किसान फल–सब्जी की खेती के साथ–साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स से भी जुड़ें, ताकि कच्चे माल से प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाकर अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सके, जैसे बासमती के उदाहरण में एक यूनिट लगने के बाद क्षेत्र में बासमती की खेती का विस्तार हुआ और किसानों की आय बढ़ी। उन्होंने बताया कि यहाँ दलहन मिशन को पूरी ताकत से लागू किया जाएगा और मध्य प्रदेश में 55 दाल मिलें खोलने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, ताकि चना, मसूर, उड़द और तुअर जैसी दालों की खेती को मजबूत बाज़ार मिले। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि किसान जितनी मसूर, उड़द और तुअर पैदा करेंगे और बेचना चाहेंगे, उतनी पूरी मात्रा भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का काम करेगी और खेती से लेकर बाजार तक की सभी कड़ियों पर चल रही योजनाओं को इस क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

नया मृदा/eFARM मोबाइल ऐप

श्री चौहान ने नए मृदा/eFARM मोबाइल ऐप का उल्लेख करते हुए कहा कि अब किसान केवल मोबाइल लेकर खेत पर घूमेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि मिट्टी में कौन–से पोषक तत्व हैं और कौन–सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है, जिससे 'रामलाल ने एक बोरी डाली तो श्यामलाल भी डाल दे' जैसी आदतों की जगह वैज्ञानिक खाद प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा, किसान अनावश्यक खाद खर्च से बचेंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे तीनों दिन पूरी गंभीरता से इन सत्रों में भाग लें, सीखें और अपनी कृषि पद्धति बदलें, क्योंकि कम जमीन पर अलग–अलग फसलों के साथ अधिक आमदनी प्राप्त करना ही इस महोत्सव का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी तीनों दिन यहीं रहकर विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे, केवल भाषण देकर लौट जाने वाले नहीं हैं, और किसान भी सूचना के अनुसार अलग–अलग सत्रों में सक्रिय भागीदारी करें।

अब शासन की कार्य–संस्कृति बदल चुकी है

म.प्र. के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि देश में अब शासन की कार्य–संस्कृति बदल चुकी है, विभाग अलग–थलग नहीं, बल्कि समन्वित और मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और यह सब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदली हुई सोच और कार्यशैली का परिणाम है। उन्होंने मंच से जोरदार तालियों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करते हुए कहा कि वे छह बार सांसद और छह बार विधायक रहे हैं और जिस भी काम को हाथ में लेते हैं, उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना उनकी पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का यह भव्य कार्यक्रम पूरे मंच के लिए गर्व की बात है, जहाँ समय भले सीमित हो, लेकिन संकल्प असीमित है। उन्होंने इस मंच को एक ओर सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और दूसरी ओर खेत में देश की अर्थव्यवस्था संभालने वाले किसानों को एक साथ सम्मान देने वाला मंच बताते हुए कहा कि यह आयोजन दोनों की गरिमा बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जहाँ देश सीमा पर सुरक्षित है और खेतों में मेहनतकश किसान भारत का मान–सम्मान बढ़ा रहे हैं।

प्रदर्शनी परिसर नगर बसने जैसा

उन्होंने उल्लेख किया कि आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में दोगुना निर्यात कर रहा है, जबकि पहले कांग्रेस के समय गेहूँ तक आयात करना पड़ता था, पर अब रायसेन अकेला 47 देशों को बासमती चावल निर्यात कर रहा है, जो किसान की मेहनत और भारत सरकार की नीतियों का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस शासन और भाजपा सरकार की तुलना करते हुए कहा कि 1956 में मध्य प्रदेश बनने के बाद लगभग 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, तब सिंचाई का रकबा सीमित था और गेहूँ का समर्थन मूल्य 90–100 रुपये प्रति क्विंटल से आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि भाजपा सरकारों श्री शिवराज सिंह चौहान, सुश्री उमा भारती, श्री बाबूलाल गौर और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गेहूँ का दाम 2625 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँचा है और सिंचाई क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, साथ ही किसानों को दिन में नियमित बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसान, महिला, गरीब और युवा- इन चार वर्गों को केंद्र में रखकर विकास की जो व्यापक नीति बनाई है, उसकी जमीनी झलक इस प्रदर्शनी और उन्नत कृषि महोत्सव में स्पष्ट दिखाई दे रही है। उन्होंने ऊपर से प्रदर्शनी परिसर को देखकर इसे नगर बसने जैसा दृश्य बताते हुए कहा कि पशुपालन, बागवानी, उन्नत कृषि यंत्र, विविध सत्रों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का यह विशाल ताना–बाना मानो हनुमान जी के विराट रूप की तरह विस्तार लिए हुए है, जो यह दिखाता है कि किसान किस–किस क्षेत्र में किस–किस प्रकार से काम कर सकता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने पूरे वर्ष को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और इस कड़ी में भारत सरकार के सहयोग से तैयार यह विशाल प्रदर्शनी और प्रशिक्षण–केन्द्रित मेला मध्य प्रदेश की कृषि को नई दिशा देगा। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सब मिलकर इस आयोजन की मूल भावना के अनुसार हर सत्र का लाभ उठाने और विकास की इस रफ्तार को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कृत–संकल्पित हैं।

मंच पर कार्यक्रम के पहले, रक्षा मंत्री के आगमन के बाद सबसे पहले कॉर्न कटर मशीन, सोलर पैनल और पंप, माइक्रो इरिगेशन और हाइड्रोजन–पावर्ड ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरणों का लाइव डेमो हुआ, इसके बाद पशुपालन, मृदा स्वास्थ्य सुधार एवं पोषण, उर्वरक (IFFCO), क्रॉप साइंस, मत्स्य पालन, राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड और CIM-MYT–BISA सहित विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कराया गया। मंच पर सांची क्षेत्र के विधायक डॉ. प्रभु राम चौधरी द्वारा स्वागत भाषण के बाद प्रदेश के कृषि मंत्री श्री एंदल सिंह कंसाना और केंद्रीय कृषि सचिव श्री अतीश चंद्रा ने भी किसानों को संबोधित किया। योजनाओं के तहत किसानों को लाभ–वितरण किया गया और साथ ही मृदा/eFARM मोबाइल ऐप लॉन्च कर किसानों को मिट्टी की सेहत की जाँच, पोषण प्रबंधन और वैज्ञानिक सिफारिशें मोबाइल पर उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई, जबकि तीन दिन तक 20 से अधिक तकनीकी सत्रों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और थीम–आधारित हॉल में किसानों को उन्नत तकनीक से रूबरू कराया जाएगा।

उद्घाटन समारोह में राज्य के पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल, उद्यान मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह पवार, जिले के मंत्री श्री नरेंद्र पटेल, नर्मदापुरम के सांसद श्री दर्शन चौधरी, अन्य सांसद-विधायक सहित वरिष्ठ नेता, किसान मोर्चा पदाधिकारी, जिला अध्यक्षगण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डीजी डॉ. एम.एल. जाट भी उपस्थित थे।

श्री महेंद्र सिंह यादव बने अपेक्स बैंक के प्रशासक

भोपाल। मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्ति में ग्वालियर निवासी श्री महेंद्र सिंह यादव को अपेक्स बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह आदेश पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल श्री मनोज पुष्प द्वारा जारी किया गया।

जारी आदेश क्रमांक साख/एपी/276/2026/752 के अनुसार, श्री यादव को दिनांक 25 अप्रैल 2026 से प्रशासक के पद पर पदस्थ किया गया है। वे श्री बाबूसिंह यादव के सुपुत्र हैं तथा मोहनपुर, मुरार (ग्वालियर) के निवासी हैं। साथ ही वे बड़ागांव सहकारी सोसाइटी के सदस्य भी हैं।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व दिनांक 14 जुलाई 2025 से प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग श्री डी.पी. आहूजा इस पद का कार्यभार संभाल रहे थे। नए प्रशासक की नियुक्ति के साथ ही अपेक्स बैंक के संचालन में प्रशासनिक स्तर पर नया नेतृत्व स्थापित हुआ है।

सहकारिता क्षेत्र के जानकारों के अनुसार, यह नियुक्ति बैंक के प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा कार्यप्रणाली में गति लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने राजोदा में गेहूं उपार्जन केंद्र का किया निरीक्षण

भोपाल। कलेक्टर ऋतुराज सिंह एवं उपायुक्त सहकारिता दीपाली खंडेलवाल द्वारा सेवा सहकारी समिति बैरागढ़ के माध्यम से संचालित मातृशक्ति वेयरहाउस क्रमांक-01, राजोदा स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान उपार्जित गेहूं की गुणवत्ता एवं तौल की जा रही बोरियों के वजन की जांच की गई। अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित किसानों से चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा वैध स्लॉट अवधि वाले शेष किसानों की तौल शीघ्र कराने के निर्देश समिति प्रबंधक को दिए। साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि एफ.ए.क्यू. मानक के अनुरूप गेहूं की खरीदी की जाए और प्रतिदिन 2250 क्विंटल उपार्जन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं—तौल कांटे, हम्माल व तुलावटी आदि—उपलब्ध रहें। उपार्जन केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में किसानों ने बताया कि पेयजल, बैठने के लिए छांव तथा शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था है। व्यवस्थाओं से संतुष्टि भी व्यक्त की गई। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर संजीव जैन, जिला आपूर्ति अधिकारी दिनेश अहिरवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जिले में उपार्जन की प्रगति

जिले में शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य 2585 रुपये एवं 40 रुपये बोनस सहित कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 136 उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी की जा रही है। अब तक कुल 77,335 पंजीकृत किसानों में से 37,019 किसानों ने स्लॉट बुक कराया है, जिनमें से 23,147 किसान अपनी उपज विक्रय कर चुके हैं। इन किसानों से कुल 9,83,140 क्विंटल गेहूं का उपार्जन किया गया है।

25 अप्रैल को 935 किसानों से लगभग 35,000 क्विंटल गेहूं खरीदा गया। भुगतान के तहत लगभग 150 करोड़ रुपये के ईपीओ प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 102.70 करोड़ रुपये किसानों के आधार लिंक खातों में सफलतापूर्वक जमा किए जा चुके हैं। शेष भुगतान प्रक्रिया जारी है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी उपार्जन केंद्रों पर प्रतिदिन 2250 क्विंटल गेहूं खरीदी की व्यवस्था की गई है। साथ ही राज्य शासन द्वारा स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर 09 मई 2026 कर दी गई है, जिससे छोटे, मध्यम एवं बड़े सभी किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज का विक्रय कर सकें।

भारत टैक्सी का मुंबई में विस्तार, चालक ऑनबोर्डिंग पहल का शुभारंभ

दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री एवं मुंबई उत्तर से सांसद पीयूष गोयल ने मुंबई में "भारत टैक्सी चालक ऑनबोर्डिंग पहल" का शुभारंभ किया। कांदिवली पश्चिम स्थित कमला विहार स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ऑटो-रिक्शा एवं टैक्सी चालक, परिवहन यूनियन प्रतिनिधि तथा सहकारी संस्थाओं के सदस्य शामिल हुए।

इस पहल का उद्देश्य चालकों को संगठित डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ते हुए उनकी आय में वृद्धि, पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा शहरी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि सहकारिता और प्रौद्योगिकी आधारित मॉडल भारत के उभरते गतिशीलता तंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि "भारत टैक्सी" के माध्यम से चालकों को भागीदार के रूप में जोड़कर उन्हें डिजिटल सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिससे उनकी आय और कार्य-गरिमा दोनों में सुधार होगा।

यह ऑनबोर्डिंग अभियान देश के प्रमुख शहरों में चालक-प्रथम (Driver-first) मोबिलिटी सिस्टम को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। प्रक्रिया को सरल बनाकर और राइड की मांग तक नियमित पहुंच सुनिश्चित कर, यह पहल चालकों एवं यात्रियों दोनों के लिए एक टिकाऊ एवं समावेशी परिवहन तंत्र विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म से 5.17 लाख से अधिक चालक जुड़ चुके हैं, जबकि 50 लाख से अधिक ग्राहक ऑनबोर्ड किए जा चुके हैं। विभिन्न शहरों में प्रतिमाह लगभग 10 लाख राइड्स संचालित की जा रही हैं। मुंबई अब उन प्रमुख शहरों में शामिल हो गया है, जहां यह सेवा पहले से संचालित है, जिनमें दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, चंडीगढ़ और लखनऊ शामिल हैं।

कार्यक्रम में भारत टैक्सी के मुख्य परिचालन अधिकारी विवेक पांडेय ने कहा कि मुंबई एक उच्च संभावनाओं वाला बाजार है और स्थानीय चालक यूनियनों के सहयोग से यहां एक मजबूत चालक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाएगा।

यह पहल अमित शाह के उस विजन के अनुरूप है, जिसके तहत आगामी तीन वर्षों में "भारत टैक्सी" को देश के सभी प्रमुख शहरों में विस्तार देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की यह पहल शहरी क्षेत्रों में तकनीक -आधारित, सहकारी एवं समावेशी परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

नरवाई जलाना खेत और सेहत दोनों के लिए हानिकारक : कृषि मंत्री

कृषि चौपाल के माध्यम से प्रदेशभर में किसान जागरूकता अभियान

भोपाल : किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि प्रदेश में नरवाई जलाने के नुकसान और नहीं जलाने के फायदों को लेकर कृषि विभाग द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुरूप 'कृषि चौपाल' के माध्यम से हर विकासखंड के गांवों में किसानों को नरवाई प्रबंधन की वैज्ञानिक जानकारी दी जा रही है।

कृषि मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि रबी कटाई के बाद अप्रैल-मई में यह अभियान तेज कर दिया गया है। वर्तमान में मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, महाकौशल, चंबल और विंध्य क्षेत्र के सभी 313 विकासखंडों में 'कृषि चौपाल' आयोजित की जा रही हैं। बड़े स्तर पर नरवाई प्रबंधन पर चर्चा हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा परियोजना

और कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से लाइव प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं।

मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि नरवाई जलाने के कई दुष्परिणाम हैं। इसे जलाने से मिट्टी की उर्वरता नष्ट होती है। लगभग 1 टन नरवाई जलाने से 5.5 किलो नाइट्रोजन, 2.3 किलो फॉस्फोरस, 25 किलो पोटाश व 400 किलो कार्बनिक पदार्थ जल जाते हैं, जिससे मित्र कीट मर जाते हैं। पर्यावरण व स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। धुएं से जहरीली गैसें बढ़ती हैं, जिससे सांस व आंखों के रोग होते हैं। दृश्यता घटने से सड़क हादसे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर नरवाई जलाना दंडनीय अपराध है और जुर्माने का प्रावधान है।

मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि नरवाई नहीं जलाने के फायदे हैं। इसे खेतों में मिलाने से भूमि की सेहत सुधरती है। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, मल्चर से नरवाई खेत में मिलाने पर जैविक कार्बन बढ़ता है, पानी रोकने की क्षमता 30 प्रतिशत बढ़ती है। किसानों को अतिरिक्त आय भी होती है। स्ट्रॉ बेलर से गट्ठर बनाकर गोशाला, पेपर मिल, बायो-सीएनजी प्लांट को बेचा जा सकता है। पराली को खेत में मिलाने से अगली फसल में 20 प्रतिशत यूरिया कम लगती है।

कृषि मूल्य श्रृंखला एवं वित्तपोषण पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम सम्पन्न

पुणे। वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में "कृषि मूल्य श्रृंखला एवं वित्तपोषण पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम" का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम Center for International Cooperation and Training in Agricultural Banking एवं VAMNICOM के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागियों ने सक्रिय सहभागिता की।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों, वित्तपोषण के आधुनिक तरीकों, सहकारिता आधारित संस्थागत ढांचे तथा कृषि वित्त प्रबंधन की व्यावहारिक समझ प्रदान करना था।

प्रथम दिवस पंजीयन एवं उद्घाटन सत्र के उपरांत ग्रामीण वित्तपोषण का अवलोकन विषय पर डॉ. डी. रवि (प्रोग्राम डायरेक्टर) द्वारा व्याख्यान दिया गया। इसके पश्चात भारत में एग्री वैल्यू चेन फाइनेंसिंग विषय पर श्री सौम्य श्री मल्ल (वाइस प्रेसिडेंट एवं रीजनल हेड, बिजनेस बैंकिंग, महाराष्ट्र) द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पुणे के विशेषज्ञों द्वारा एग्री वैल्यू चेन फाइनेंसिंग में NABARD की भूमिका तथा एवीसी फाइनेंसिंग के दायरे एवं जोखिम प्रबंधन पर व्याख्यान प्रस्तुत किए गए।

द्वितीय दिवस पर प्रतिभागियों हेतु अध्ययन भ्रमण आयोजित किया गया। इस क्रम में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का भ्रमण कर एग्री वैल्यू चेन फाइनेंसिंग में NCDC की भूमिका को समझा गया। साथ ही पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का भ्रमण कराया गया, जहाँ बैंक अधिकारियों द्वारा बैंकिंग संचालन, ऋण वितरण प्रणाली एवं किसानों तथा सहकारी संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। दोपहर पश्चात सत्र में FPO मॉडल के अनुभव विषय पर श्री विजय ठुबे (शाश्वत FPO, पुणे) द्वारा व्यावहारिक जानकारी साझा की गई तथा डॉ. अभय गायकवाड़ द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन मंडल (MSAMB), पुणे द्वारा स्मार्ट प्रोजेक्ट की एग्री वैल्यू चेन पहले विषय पर प्रस्तुति दी गई। तृतीय दिवस पर कृषि विज्ञान केंद्र, बारामती का भ्रमण कराया गया, जहाँ कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीज, फसल प्रबंधन, जैविक खेती एवं कृषि आधारित उद्यमों पर जानकारी दी गई तथा डेमो प्लॉट्स के माध्यम से व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अंतिम दिवस डॉ. डी. रवि द्वारा पूर्व सत्रों का पुनरावलोकन प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के विशेषज्ञों द्वारा एग्री वैल्यू चेन फाइनेंसिंग में RBI की भूमिका पर व्याख्यान दिया गया। प्रतिभागियों द्वारा एक्शन प्लान निर्माण एवं कंट्री पेपर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए गए, जिनमें अपने-अपने क्षेत्रों में इस मॉडल के क्रियान्वयन की संभावनाओं को साझा किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल से कुल 03 प्रशिक्षकों को नामांकित किया गया, जिनमें से 02 प्रशिक्षक भोपाल से एवं 01 प्रशिक्षक जबलपुर से शामिल हुए।

कार्यक्रम का समापन मूल्यांकन, फीडबैक एवं वैलिडिक्शन सत्र के साथ हुआ, जिसमें डॉ. सुवा कांता मोहंती द्वारा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की उपलब्धियों एवं कृषि वित्त पोषण के भविष्य के आयामों पर प्रकाश डाला गया।

यह प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक भ्रमण प्रतिभागियों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी सिद्ध हुआ, जिससे उन्हें कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण एवं सहकारिता क्षेत्र के व्यावहारिक पहलुओं को समझने में महत्वपूर्ण सहायता मिली।

पीजीडीएम (कृषि व्यवसाय प्रबंधन) प्रवेश प्रक्रिया हेतु जबलपुर में समूह चर्चा एवं साक्षात्कार सम्पन्न

भोपाल। वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पुणे द्वारा संचालित पीजीडीएम (कृषि व्यवसाय प्रबंधन) पाठ्यक्रम सत्र 2026–2028 के लिए प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, जबलपुर में समूह चर्चा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

इस चयन प्रक्रिया में विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए अभ्यर्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान अभ्यर्थियों की प्रबंधकीय क्षमता, विषयगत ज्ञान, अभिव्यक्ति कौशल एवं नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन समूह चर्चा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया गया।

चयन प्रक्रिया में पैनल सदस्य के रूप में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, जबलपुर के प्राचार्य श्री व्ही.के. बर्वे, सहकारिता विभाग जबलपुर के प्रभारी उपायुक्त श्री प्रशांत कौरव, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉ. दीपक राठी तथा संयुक्त कार्यक्रम निदेशक डॉ. डी. रवि उपस्थित रहे। विशेषज्ञों द्वारा अभ्यर्थियों का गहन मूल्यांकन करते हुए उन्हें कृषि व्यवसाय एवं सहकारिता क्षेत्र की संभावनाओं एवं चुनौतियों से भी अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के सफल संचालन में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, जबलपुर के श्री जय कुमार दुबे, प्रशिक्षक श्री अखिलेश उपाध्याय, श्री एन.पी.ए. दुबेएवं श्रीमती उमा भूमरकर (लिपिक) का सहयोग रहा।

यह प्रवेश प्रक्रिया युवाओं को कृषि व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट अवसर प्रदान करने के साथ-साथ सहकारिता आधारित कृषि एवं व्यवसायिक तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। विशेषज्ञों ने विश्वास व्यक्त किया कि इस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित युवा भविष्य में कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र में नवाचार एवं विकास को नई दिशा प्रदान करेंगे।

दुग्ध सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु टीला में प्रशिक्षण कार्यक्रम

भोपाल। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव (जिला छतरपुर) द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, टीला (जिला अशोकनगर) में एक दिवसीय सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण वर्ग का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को सहकारिता के सिद्धांतों, संगठनात्मक प्रबंधन एवं व्यवसायिक दक्षता के प्रति जागरूक करना था।

प्रशिक्षण वर्ग में समिति के सचिव श्री अरविंद यादव, सदस्य श्री नंदकिशोर यादव, श्रीमती सीमा यादव सहित अन्य सदस्य एवं कृषक/दुग्ध उत्पादक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक श्री बाबूलाल कुशवाहा द्वारा किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सहकारिता आंदोलन की पृष्ठभूमि, उसके मूल सिद्धांतों एवं दुग्ध सहकारी समितियों की भूमिका पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही समिति के प्रभावी संचालन, पारदर्शिता, लेखा-प्रबंधन, सदस्य सहभागिता, दुग्ध संकलन एवं विपणन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उपायों पर विशेष चर्चा की गई।श्री कुशवाहा ने बताया कि सहकारिता के माध्यम से छोटे एवं सीमांत दुग्ध उत्पादक भी संगठित होकर बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने, गुणवत्ता सुधार एवं समयबद्ध भुगतान व्यवस्था पर भी जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं एवं अनुभवों को साझा किया, जिनका समाधान प्रशिक्षण के माध्यम से किया गया।कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।